



वित्त मंत्रालय

‘पनामा पेपर्स’ से जुड़े मामले : तेजी से हो रही है जांच-पड़ताल

Posted On: 06 NOV 2017 3:42PM by PIB Delhi

वाशिंगटन स्थित एक संगठन ‘खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम (आईसीआईजे)’ द्वारा अप्रैल 2016 में कोई कर नहीं/कम कर वाले क्षेत्राधिकारों में अवस्थित विदेशी निकायों से कुछ भारतीयों के जुड़े होने के बारे में किए गए खुलासे के बाद सरकार ने 4 अप्रैल, 2016 को एक मल्टी-एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया था, ताकि अन्य बातों के अलावा समन्वित एवं त्वरित ढंग से जांच-पड़ताल संभव हो सके। एमएजी में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल थे। एमएजी ने अब तक 7 रिपोर्ट सरकार को पेश की हैं।

‘पनामा पेपर्स’ में प्रथम दृष्टया लगभग **426** भारतीयों अथवा भारतीय मूल के लोगों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। आयकर विभाग ने अन्य बातों के अलावा **28** विदेशी क्षेत्राधिकारों का **395** बार संदर्भ देते हुए सभी **426** मामलों में पूछताछ की है। प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण और की गई जांच के आधार पर अब तक जो निष्कर्ष सामने आए हैं उनसे **147** कार्रवाई योग्य मामलों और **279** गैर-कार्रवाई योग्य मामलों (अनिवासी/कोई अनियमितता नहीं, इत्यादि) के बारे में संकेत मिले हैं।

147 कार्रवाई योग्य मामलों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- विभिन्न जांच प्रक्रियाओं से अब तक लगभग **792** करोड़ रुपये के अघोषित ऋणों के बारे में पता चला है।
- **35** मामलों में तलाशियां ली गई हैं और **11** मामलों में निरीक्षण किया गया है।
- अन्य मामलों में पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्तियों के समक्ष साक्ष्य भी पेश किए गए।
- **5** मामलों में आपराधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।
- **7** मामलों में काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसम्पत्तियां) और टैक्स आरोपण अधिनियम 2015 की धारा 10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।
- उपर्युक्त सभी मामलों में आगे की जांच प्रगति पर है।

वीके/आरआरएस/वीके- 5339

(Release ID: 1508504) Visitor Counter : 16

